MR. CHAIRMAN: It's all right. ...*(Interruptions)*... Give a notice. ...*(Interruptions)*... There is no problem with it. ...*(Interruptions)*... Thank you.

हिमाचल प्रदेश पर्यटन के लिए धनराशि

+*62. **श्रीमती बिमला कश्यप सूद** : क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लिए 104 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं और उन्हें कब स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि एशियाई विकास बैंक ने भी हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 95 करोड़ रुपये की धनराशि व्यय की है;

(घ) यदि हां, तो यह धनराशि कब और कहां-कहां व्यय की गई है तथा उससे संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2011-12 के दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश को कुल कितनी धनराशि आबंटित की जा रही है?

पर्यटन मंत्री (**श्री सुबोध कांत सहाय**): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) पर्यटन परियोजनाओं का विकास, संवर्धन, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय निधियों की उपलब्धता तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पहले जारी की गई निधियों के संबंध में उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत किए जाने की शर्त पर, राज्य सरकारों के साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त एवं योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्ण पर्यटन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

पर्यटन मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के विकास और संवर्धन के लिए 11वीं योजना में मार्च, 2011 तक 40 परियोजनाओं के लिए रु.128.32 करोड़ स्वीकृत किए हैं। परियोजनाओं की सूची विवरण-I में दी गई है। (नीचे **देखिए**)।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम हेतु एशियाई विकास बैंक के साथ दिनांक 20.7.2011 को एक ऋण करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस पहल के तहत, 33.00 मिलियन यू.एस. डालर की ट्रेंच-I अनुमोदित की गई है और कार्य निष्पादित किए जा रहे हैं।

विवरण-I

11वीं योजना में (31.03.2011 तक) हिमाचल प्रदेश के लिए स्वीकृत की गई परियोजनाएं:-

(रु. लाख में)

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	2
	2007-08	
1	स्पीति-संगला-50.00, किन्नौर 173.00, स्पीति-210, लाहौल-160, पांगी-75, एल.के. एंटायर सर्किट-30 में इको पर्यटन पर विशेष फोकस के साथ आदिवासी परिपथ का एकीकृत विकास	698.00
2	हिमाचल प्रदेश में इको पर्यटन का विकास	368.22
3	आउटर सेराज का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में एकीकृत विकास	380.00
4	शिहुंता-समोजे-जॉट का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में एकीकृत विकास	355.00
5	मणि महेश का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में एकीकृत विकास	400.00
6	माउंटेन बाइकिंग इवेंट, 2007	10.00
7	हिमालयन एडवेंचर रेस 2007	5.00
8	कुल्लू दशहरा फेस्टिवल	5.00
9	शिमला समर फेस्टिवल	5.00
10	ग्रेट हिमालयन मैराथन	5.00
11	पर्यटक आकर्षण पर सीडी रोम्स और वी.सी.डी. को तैयार करना और कम्प्यूटरीकरण	50.00
12	आई एच एम, हमीरपुर	1200.00
	कुल	3481.22
	2008-09	
1	ऊना-बिलासपुर-हमीरपुर परिपथ का एकीकृत विकास	760.00
2	हमीरपुर का एक पर्यटक परिपथ के रूप में एकीकृत विकास	600.00
3	सोलन जिले का एक परिपथ के रूप में एकीकृत विकास	420.00
4	चैल का एक गंतव्य के रूप में एकीकृत विकास	480.00

1	2	3
5	जोगिन्दर नगर और बीर बिलिंग का एक गंतव्य के रूप में एकीकृत विकास	427.90
6	नलधेरा का एक गंतव्य के रूप में एकीकृत विकास	269.76
7	मिन्जार फेयर चम्बा, 2008 का आयोजन	5.00
8	माउंटन बाइकिंग इवेंट एम टी बी 2008	10.00
9	कुल्लू दशहरा और मिनार फेयर के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	10.00
10	एफ.सी.आई. धर्मशाला	475.00
	कुल	3457.66
	2009-10	
1	हिमाचल प्रदेश में ऑफ बीट गंतव्य का एकीकृत विकास	750.00
2	हिमाचल प्रदेश में शिमला-थिओग-नरकंडा का एक पर्यटक परिपथ के रूप में एकीकृत विकास	750.00
3	हिमाचल प्रदेश में जुब्बल और कोटखाई का एकीकृत विकास	405.00
4	सुंदरनगर का एकीकृत विकास	475.00
5	माउंटेन बाइकिंग इवेंट, 2009 के आयोजन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	10.00
6	सेलीब्रेशन ऑफ मिंजार फेयर, 2009	5.00
	कुल	2395.00
	2010-11	
1	जुबेरहाटी-अरकी-नालागढ़ का एक पर्यटक परिपथ के रूप में विकास	800.00
2	हिमाचल प्रदेश में एक पर्यटक परिपथ के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	693.64
3	स्वरघाट-धाजेस-धूमरविन-सरकाघाट का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में विकास	495.00
4	हिमाचल प्रदेश में धरमपुर, तहसील-सरकाघाट, जिला मंडी में शीतला माता काम्पलेक्स के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	151.70
5	हिमाचल प्रदेश में सरकाघाट, जिला मंडी में लागू हरिद्वार, कंडापत्तन के विकास के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	302.44
6	धौलाधर (कांगडा नगरौटा बैजनाथ पोंग) का एक पर्यटक गंतव्य के रूप में एकीकृत विकास	423.00

1	2	3
7	हिमाचल प्रदेश में पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड-कप 2010 के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	10.00
8	हिमाचल प्रदेश में माउंटेन बाइकिंग इवेंट 2010 के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	5.00
9	हिमाचल प्रदेश में कुल्लू दशहरा फेस्टिवल 2010 के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता	5.00
10	शिमला समर फेस्टिवल 2010 मनाना	5.00
11	आई टी योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश की वेबसाइट की रिवैम्पिंग	15.00
12	हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में जमुना नगर - पंचकुला-पोंटा साहिब वृहत परियोजना का विकास	592.00
	कुल	3497.78
	कुल योग	12831.66

Funds for Himachal Pradesh tourism

†*62. SHRIMATI BIMLA KASHYAP SOOD: Will the Minister of TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has sanctioned projects of Rs.104 crore for the State Government of Himachal Pradesh to promote tourism;

(b) if so, the names of the said projects and when these were sanctioned;

(c) whether it is a fact that Asian Development Bank has also spent Rs. 95 crore for promoting tourism in Himachal Pradesh;

(d) if so, when and where, along with the details thereof; and

(e) the total amount of funds being allocated to Himachal Pradesh for tourism during the year 2.011-12?

THE MINISTER OF TOURISM (SHRI SUBODH KANT SAHAI): (a) to (e) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (e) Development, promotion, implementation and monitoring of tourism projects is primarily undertaken by the State Governments/UTs. However, Ministry of Tourism provides Central Financial Assistance (CFA) for tourism projects, which are complete as per scheme guidelines and prioritized in consultation with the State Government, subject to availability of funds and submission of utilization certificates for funds released earlier under various schemes.

†Original notice of the question was received in Hindi.

Ministry of Tourism has sanctioned 40 projects for ì 128.32 crore in 11th Plan upto March 2011 for development and promotion of tourism in Himachal Pradesh. The list of projects is given in the Statement-I (*See* below).

As per the report received from State Government of Himachal Pradesh, a loan agreement with the Asian Development Bank has been signed on 20.7.2011 for infrastructure Development Investment Programme for tourism in Himachal Pradesh. Under this initiative, Trench-I of US $33.00 million has been approved and works are being executed.

Statement-I

Projects sanctioned to the Himachal Pradesh during the 11th plan (upto 31.03.2011)

(ì in lakh)

Sl. No.	Name of the Project	Amount Sanctioned
1	2	3
	2007-08	
1.	Integrated development of Tribal Circuit with special focus on Eco Tourism at Spiti-Sangla-50.00, Kinnaur 173.00, Spiti-210, Lahaul-160 Pangi-75, LK Entire circuit-30	698.00
2.	Development of Eco-Tourism in Himachal Pradesh	368.22
3	Integrated development of Outer Seraj as a tourist destination	380.00
4	Integrated development of Shihunta-Samote-Jot as a tourist destination	355.00
5	Integrated development of Mani Mahesh as a tourist destination	400.00
6	Mountain Biking Event, 2007	10.00
7	Himalayan Adventure Race 2007	5.00
8	Kullu Dussehra Festival	5.00

1	2	3
9.	Shimla Summer Festival	5.00
10	Great Himalayan Marathan	5.00
11	Computerization and production of CD ROMs and VCDs on the Tourist attraction	50.00
12	IHM Hamirpur	1200.00
	Total	3481.22
	2008-09	
1.	Integrated development of Una-Bilaspur-Hamirpur circuit	760.00
2.	Integrated development of Hamirpur as a tourist circuit	600.00
3.	Integrated development of Solan District as a circuit	420.00
4.	Integrated development of Chail as a destination	480.00
5.	Integrated development of Joginder Nagar Bir Billing as a destination	427.90
6.	Integrated development of Naldhera as a destination	269.76
7.	Organizing of Minjar Fair Chamba, 2008	5.00
8.	Mountain Biking Event MTB 2008	10.00
9.	CFA for Kullu Dusshera and Minar Fair	10.00
10.	FCI Dharamshala	475.00
	Total	3457.66
	2009-10	
1.	Integrated Dev. of Off Beat Destination in H.P.	750.00
2.	Integrated Dev. of Shimla-Theog-Narkanda as a Tourist Circuit in H.P.	750.00
3.	Integrated Dev. of Jubbal and Kotkhai in H.P.	405.00
4.	Integrated Development of Sundernagar	475.00

1	2	3
5.	CFA for organization of Mountain Biking Event, 2009	10.00
6.	Celebration of Minjar Fair 2009	5.00
	Total	2395.00
	2010-11	
1.	Development of Jubberhati-Arki-Nalagarh as a tourist circuit	800.00
2.	CFA for Development of Rural Areas as a tourist circuit in H.P.	693.64
3.	Development of Swarghat- Ghages-Ghumarwin-Sarkaghat as a tourist destination	495.00
4.	CFA for the Development of Sheetla Mata Complex at Dharampur Tehsil-Sarkaghat, Dist. Mandi in H.P.	151.70
5.	CFA for Development of Lagoo Haridwar Kandapattan in The. Sarkaghat, Dist. Mandi in H.P.	302.44
6.	Integrated Development of Dhauladhar (Kangra Nagrota Baijnath Pong as a Tourist Destination	423.00
7.	CFA for Paragliding Pre-world Cup- 2010 in H.P.	10.00
8.	CFA for Mountain Biking Event 2010 in H.P.	5.00
9.	CFA for Kullu Dussehra Festival 2010 in H.P.	5.00
10.	Celebration of Shimla Summer Festival 2010	5.00
11.	Revamping of Website of Himachal Pradesh under the IT scheme	15.00
12.	Development of Jamuna Nagar-Panchkula-Poanta Sahib Mega Project in HP & Haryana	592.00
	TOTAL	3497.78
	GRAND TOTAL	12831.66

श्रीमती बिमला कश्यप सूद: सभापति जी, हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों के आने-जाने के लिए एकमात्र सुविधा सड़क की है। पहाड़ी क्षेत्र के होने के कारण यहां आने-जाने में बहुत समय लगता है। वर्ष 2010 में प्लानिंग कमीशन

के साथ हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्य मंत्री जी की बैठक हुई थी और उसमें हैली टैक्सी चलाने की योजना को मंजूरी दी गई थी। हिमाचल प्रदेश में हैली टैक्सी आरंभ कर दी गई। Viability Gap Funding Scheme द्वारा केन्द्र सरकार ने इसमें मदद करनी थी। हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यह बहुत आवश्यक है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या हैली टैक्सी के लिए केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को फंड देने की कोई योजना है?

श्री सुबोध कांत सहाय: सभापति जी, हमारे पास अभी तक इसके लिए कोई official proposal नहीं आया है। जो भी proposal आता है, हर साल का prioritization होता है। उस लिहाज़ से हिमाचल में हैली टैक्सी चले, यह उस बैठक में principally जरूर तय हुआ होगा, क्योंकि एक hilly state के लिए हेलीकॉप्टर, कम्युनिकेशन के माध्यम के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन हिमाचल सरकार की तरफ से हमारे पास अभी तक इस तरह का कोई प्रपोज़ल नहीं आया है। अगर प्रपोज़ल आएगा, तो निश्चित तौर पर हम इस पर विचार करेंगे।

श्रीमती बिमला कश्यप सूद: सभापति जी, मेरी जानकारी के हिसाब से जो यह प्रपोज़ल 2010 में आया है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कुल्लू-मनाली मैगा प्रोजेक्ट के लिए 50 करोड़ रुपए की स्वीकृति आपने सैद्धांतिक रूप से दी है, जो world famous valley and natural beauty के डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन अभी तक वह पैसा नहीं मिला है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि वह पैसा कब तक हिमाचल सरकार को मिलेगा?

श्री सुबोध कांत सहाय: सभापति जी, इस साल हमने 2011-12 के लिए जो prioritization किया है, इसकी स्कीम हमें जुलाई के महीने में मिली है। इस पूरी DPR को judge करके हम उसका पैसा रिलीज़ करेंगे। इसलिए कोई देरी उसमें नहीं हुई है, जुलाई में ही यह revised DPR आई है।

श्रीमती विप्लव ठाकुर: सभापति जी, मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देती हूं कि हिमाचल प्रदेश में टूरिज़म के विकास के लिए वे काफी पैसा दे रहे हैं और इसके लिए उन्होंने विभिन्न योजनाएं भी बताई हैं, जिनके लिए उन्होंने पैसा दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहती हूं कि हिमाचल प्रदेश, पर्यटन के लिए बहुत बड़ा स्थान है, यहां पर बहुत से मंदिर भी हैं और यहां adventure tourism भी है। मैं यह जानना चाहती हूं कि क्या हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी यहां टूरिज्म को डेवलप करने के लिए कोई बजट रखा है, क्या उनकी भी इसको डेवलप करने की कोई priority है या वे केवल केन्द्र के ऊपर ही निर्भर रहते हैं? केन्द्र सरकार वहां टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठा रही है?

श्री सुबोध कांत सहाय: सभापति जी, मुझे लगता है कि यह high time है कि स्टेट को टूरिज्म को अपने social, political and economic agenda का part बनाना होगा, क्योंकि टूरिज्म सबसे ज्यादा employment oriented sector है, यहां से revenue भी सबसे ज्यादा आती है और इससे देश की branding होती है। आज का टूरिस्ट, कल का investor भी हो सकता है। मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं कि राज्य सरकार का बजट क्या है,

लेकिन मैं निश्चित तौर पर यह कहना चाहता हूं कि हमारी पूरी कोशिश है कि राज्य सरकारों को इसके लिए सेंसिटाइज़ किया जाए। हम खुद भी राज्यों का दौरा कर रहे हैं और टूरिज्म के लिए एक फिगर और दो फिगर के बजट को राज्य सरकारों को बढ़ाना चाहिए।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल: सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज पूरे विश्व की प्राथमिकता टूरिज्म है और विश्व के तमाम देशों की आर्थिक स्थिति टूरिज्म पर ही निर्भर करती है। जैसा मंत्री जी ने कहा है कि अगर राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव आएगा, तो उसको टूरिज्म विकास में लेंगे, अगर नहीं आएगा, तो उसको नहीं लेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आप ऐसी कोई integrated scheme बनाना चाहते हैं, जिससे इस देश के जो मुख्य-मुख्य पर्यटन स्थल हैं, उनको हम केन्द्र सरकार के माध्यम से विकसित करें, जिससे देश में टूरिज्म को बढ़ावा मिले, रोज़गार के अवसर बढ़ें और देश की आमदनी भी बढ़े?

श्री सुबोध कांत सहाय: सभापति जी, माननीय सदस्य के माध्यम से मैं हाउस को बताना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी के सामने हमने अपना futuristic plan दिया है, जिसको मैं 12th Five Year Plan में लाना चाहता हूं। जो JNNURM pattern है या Delhi-Mumbai Corridor Pattern है, उसके आधार पर इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर के integrated development के बाद हर राज्य में कुछ ऐसे destinations बनाए जाएं, जहां टूरिस्ट आएं और जहां उनको hold करके रखा जा सकता है। क्योंकि दो-चार दिन जब तक नहीं रुकेंगे, तब तक इकानॉमिकली वह फीज़िबल नहीं होता है, वहां के होटल्स और दूसरे सैक्टर्स के लिए, इसलिए इस पर बहुत बड़ा कदम उठाया जा रहा है और उम्मीद है कि जो blessing है प्राइम मिनिस्टर जी का, उससे इस सैक्टर को काफी बढ़ावा मिलेगा।

डा. विजयलक्ष्मी साधौ: सर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि बहुत सारे जो टूरिज्म स्पॉट्स हैं, वे कहीं न कहीं किन्हीं प्राइवेट ट्रस्टों के पास हैं और वे मॉन्यूमेंट्स देश के लिए बहुत वैल्यूअबल हैं। जैसा माननीय सदस्यों ने कहा कि टूरिज्म इकानॉमी डेवलप करने का एक सबसे बड़ा माध्यम बनता जा रहा है, तो माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूं कि जिन प्राइवेट संस्थाओं के पास, ट्रस्टों के पास हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, क्या उसकी ओर पर्यटन मंत्री जी ध्यान देंगे और जो मॉन्यूमेंट्स खराब हो रहे हैं, उनको अपने प्रोटैक्शन में लेकर सुधारने की व्यवस्था करेंगे?

श्री सुबोध कांत सहाय: सभापति महोदय, जो मॉन्यूमेंट्स हैं, नॉर्मली वे हमारे मंत्रालय में डायरेक्ट नहीं आते हैं, लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपटी होल्डर्स हैं, वे अगर अपने मॉन्यूमेंट्स को टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर डेवलप करना चाहते हैं, तो उनको हम डेवलप कर रहे हैं और इस तरह से देश में, खासकर राजस्थान वगैरह में जो हो रहा है, जितने लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उनको डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जो हैरिटेज प्रॉपर्टी है, उसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा देखा जाता है और उसके तहत वह आता है। उसके अपने नार्म्स हैं, उसके आधार पर उसको वह डील करता है।

श्री सभापति: थैंक यू, प्रश्न संख्या 63 ...(**व्यवधान**)...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ: माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में, महेश्वर में नर्मदा नदी के जो घाट हैं ...

MR. CHAIRMAN: No supplementaries on supplementaries. ...*(Interruptions)*... No, please. Please resume your place. ...*(Interruptions)*...

डा. विजयलक्ष्मी साधौ: माननीय सभापति महोदय, वे बहुत खूबसूरत घाट हैं, वे डैमेज हो रहे हैं।

MR. CHAIRMAN: Please resume your place. Question No.63.

दिल्ली और बिहार में प्रति व्यक्ति मासिक आय

*63. **श्री राम जेठमलानी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि आज भी देश के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में अत्याधिक अन्तर बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली और बिहार में प्रति व्यक्ति मासिक आय में बहुत अधिक अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो क्रमशः दिल्ली और बिहार में प्रति व्यक्ति मासिक आय कितनी-कितनी है; और

(घ) उक्त राज्यों में क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति मासिक आय कितनी-कितनी है और क्या बारहवीं पंच-वर्षीय योजना में प्राथमिकता के आधार पर इस अन्तर को समाप्त किया जाएगा?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) जी हां। वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 हेतु वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) द्वारा मापी गई विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय (पीसीआई) विवरण-I पर दी गई है (नीचे देखिए)। वर्ष 2010-11 के दौरान बिहार के लिए अनुमानित 20069 रुपये की तुलना में दिल्ली की पीसीआई 135814 रुपये अनुमानित है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के पहले चार वर्षों के दौरान बिहार की पीसीआई की औसत विकास दर दिल्ली के साथ तुलनीय है। वास्तव में, इस अवधि के दौरान दिल्ली की 14.66% पीसीआई विकास दर की तुलना में बिहार ने 18.4% की वार्षिक औसत पीसीआई विकास दर हासिल की है।

(घ) ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के बीच राज्य विशिष्ट पीसीआई के वितरण संबंधी डेटा संग्रहित नहीं हुआ है, तथापि, प्रत्येक राज्य के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) का ग्रामीण शहरी क्षेत्र वार वितरण